देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 27.10.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस; प्राप्त राशि से वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन को मिलेगी गति।
- राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि; पिछले तीन सालों में प्रदेश में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे।
- प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों की लंबित राज सहायता की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी।
- देहरादून शहर में बिजली, पेयजल जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए सड़क खोदने की अनुमति केवल रात के समय ही दी जाएगी; मानकों का उल्लंघन करने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी।

ग्रीन सेस

उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए "ग्रीन सेस" लागू करने की घोषणा की है। यह टैक्स बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से वसूला जाएगा, जिससे प्राप्त धनराशि वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन पर खर्च की जाएगी।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि देहरादून में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सड़क की धूल है, जो लगभग 55 प्रतिशत प्रदूषण का स्रोत है, जबकि 7 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों से होता है। ग्रीन सेस के जरिए सड़क धूल नियंत्रण और स्वच्छ वाहन नीति को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के "स्वच्छ वायु सर्वेक्षण– 2024" में ऋषिकेश को 14वां और देहरादून को 19वां स्थान मिला है। राज्य सरकार इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करने के लिए ग्रीन सेस से प्राप्त राजस्व का उपयोग करेगी।

ग्रीन सेस के तहत इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सोलर और बैटरी चालित वाहनों को छूट दी जाएगी। इससे राज्य को लगभग 100 करोड़ रुपये वार्षिक आय होने का अनुमान है।

पर्यटन प्रगति

राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले तीन सालों में प्रदेश में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं, जिससे होम स्टे, होटल, ढाबा संचालकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और परिवहन कारोबारियों की आजीविका को नया सहारा मिला है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार वर्षभर पर्यटन और तीर्थाटन गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास कर रही है।

पर्यटन विभाग के अनुसार, राज्य में पर्यटन अब बहुआयामी हो गया है। अब पर्यटक केवल प्रमुख हिल स्टेशनों तक सीमित नहीं, बल्कि छोटे और दूरस्थ स्थलों तक भी पहुंच रहे हैं। राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग और पर्वतारोहण जैसी साहसिक गतिविधियों में भी देशी–विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे प्रदेश के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिले हैं। इस समय राज्य में छह हजार से अधिक होम स्टे संचालक बढ़ी हुई पर्यटन गतिविधियों के लाभार्थी बने हैं।

प्रदेश में तीर्थाटन गतिविधियों में भी तेजी आई है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के करीब पहुंच गई है। केदारनाथ और यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 4 हजार 300 से अधिक घोड़े–खच्चर संचालकों ने अपनी सेवाएं दी हैं।

टी–टूरिज्म

चंपावत जिले का शिलिंगटाक चाय बागान अब पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ–साथ सरकार की आय का एक बड़ा जरिया भी बन गया है। वर्ष 2005 में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ने शिलिंगटाक में दो हेक्टेयर क्षेत्र में चाय बागान विकसित किया था। टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने इसे चार हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित करने की योजना बनाई।

चाय विकास बोर्ड चंपावत के प्रभारी सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत टी गार्डन में तीन कॉटेज, व्यू प्वाइंट, टी कैफे और बुटीक का निर्माण किया गया है। टी कैफे को लीज पर दिया गया है और पर्यटकों से 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क लिया जाता है। उन्होंने बताया कि 2023 से अब तक लगभग 40 हजार से अधिक पर्यटक यहां आ चुके हैं, जिससे सरकार को अच्छी आय हो रही है और चाय की बिक्री भी बढ़ी है।

पर्यटकों ने इस क्षेत्र के स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा चंपावत में टी गार्डन के विस्तार के लिए 18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 90 कॉटेज, व्यू प्वाइंट, ध्यान केंद्र और टी कैफे जैसी सुविधाओं का निर्माण प्रस्तावित है। यह

परियोजना भविष्य में चंपावत को टी टूरिज्म के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सेब सब्सिडी– भौतिक सत्यापन

प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों की लंबित राज सहायता की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कल प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त और सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ बैठक कर मिशन एप्पल (2016–17 से 2022–23) और सेब की अति सघन बागवानी योजना (2023–24) के लाभार्थी किसानों की लंबित सब्सिडी भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि राज सहायता जारी करने की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं। श्री बर्धन ने बताया कि वर्ष 2025–26 के लिए सेब बागवानी योजना के तहत 35 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि की भी व्यवस्था की जाएगी।

मुख्य सचिव ने सभी मुख्य जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिए कि 27 अक्टूबर से ही किसानों की लंबित सब्सिडी के भुगतान हेतु भौतिक सत्यापन और आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी जाए।

प्रशासन निर्णय

देहरादून शहर में अब बिजली, पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए सड़क खोदने की अनुमति केवल रात के समय ही दी जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय और मानकों का उल्लंघन करने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 नवंबर के बाद सभी एजेंसियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही निर्माण कार्य कर सकेंगी। कार्य पूरा होने के बाद सड़क को समतल और आवागमन योग्य बनाना अनिवार्य होगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन के त्वरित प्रक्रिया दल, सभी स्थलों पर निगरानी रखेंगे। अनुमति से अधिक खुदाई, बैरिकेडिंग की कमी या सड़क अधूरी छोड़ने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उपकरण जब्त किए जाएंगे।

और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस लगाए जाने की ख़बर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है– उत्तराखंड में ग्रीन सेस; दिसंबर से बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों पर राज्य में लगेगा सेस। नवोदय टाइम्स लिखता है– उत्तराखंड में ग्रीन सेस लागू करने की तैयारी पूरी, फास्ट टैग से कटेगा, लगेंगे सोलह स्थानों पर ए.एन.पी.आर कैमरे।

कर चोरी से जुड़ी ख़बर को दैनिक जागरण ने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। समाचार पत्र ने शीर्षक दिया है– हरिद्वार में चार फर्मों पर छापेमारी, आठ करोड़ की कर चोरी पकड़ी। फर्जी बिलिंग के जरिये यह कंपनियां ले रही थीं इनपुट टैक्ट क्रेडिट का लाभ।

एक अन्य ख़बर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है मुख्यमंत्री ने रिखणीखाल को दी एक सौ दो दशमलव आठ–दो करोड़ रुपए की सौगात; अब समाजसेवी गुणानंद के नाम से जाना जाएगा राजकीय इंटर कॉलेज रिखणीखाल।

उत्तराखंड में पहली बार होगी कौशल जनगणना, अमर उजाला का शीर्षक है। समाचार पत्र के अनुसार इसके लिये कौशल विकास समिति ने तैयारी शुरू कर दी है और इससे युवाओं के लिये रोजगार की राह मजबूत होने की उम्मीद है।

दून–मसूरी मार्ग पर जाम से आफत, पर्यटकों के साथ एम्बुलेंस भी फंसी, हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है। समाचार पत्र के अनुसार आपदा के बाद ग्लोगी के पास मार्ग संकरा होने के कारण आवाजाही में परेशानी हो रही है।